

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 01 जून, 2015

विषय:- प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मत्स्य विभाग से सम्बन्धित कार्यों के पुनर्निर्माण/गतिविधियों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित आपके पत्र संख्या-476/आपदा/2014-15, दिनांक 07 अगस्त, 2014 व राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-787/रा0यो0आ0/2014, दिनांक 18 जुलाई, 2014 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त/आई0डी0सी0 की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2014 को विशेष आयोजनागत सहायता (पुनर्निर्माण)/(SPA-R) के सम्बन्ध में आयोजित हाई पावर्ड कमेटी में संस्तुत मत्स्य विभाग के 02 कार्यों हेतु पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रावली संख्या-07(51)/2010 T.C के माध्यम से निम्न प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये गये हैं :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित धनराशि	आवंटित धनराशि
1	मत्स्य प्रक्षेत्र गंगोरी, उत्तरकाशी का पुनर्निर्माण।	63.33	63.18
2	मत्स्य प्रक्षेत्र बैरांगना, चमोली का पुनर्निर्माण	90.00	85.67
	योग:-	153.33	148.85

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव ₹ 153.33 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पाई गयी धनराशि ₹ 149.90 लाख के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बादल फटने एवं बाढ़ आदि के कारण भारत सरकार द्वारा आपदाग्रस्त जनपदों के लिये विशेष योजनागत सहायता हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग की अनुदान संख्या-6, लेखाशीर्षक-2245, एस0पी0ए0, 2013 के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 में मत्स्य विभाग के अंतर्गत उपरोक्त योजनाओं हेतु वित्त विभाग (टी0ए0सी0) द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि ₹ 149.90 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ₹ 63.18 + 85.67 कुल ₹ 148.85 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत किया जाय, जिनके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 3- धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।
- 4- धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये न छोड़ी जाय।
- 5- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त्युक्ति, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 6- यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जाय।
- 7- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 8- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10- त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
- 11- विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
- 13- उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत कार्य/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।
- 14- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु पशुपालन विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग निदेशक पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

15- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0104-एस.पी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.-26 P/XXVII(5)/2015, दिनांक 17 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

संख्या- [604] (1)/XVIII-(2)/15-4(15)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
- 8- बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 9- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 10- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

